







- 45 A  
Ex. राज्य सभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों की रक्षा करना है। समवर्ती सूची के मामलों में, संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं।
- 46 C  
Ex.
- 47 D  
Ex. संविधान राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है। तदनुसार, संसद एक विधान परिषद (जहां यह पहले से मौजूद है) को समाप्त कर सकती है या इसे बना सकती है (जहां इसका अस्तित्व नहीं है), यदि संबंधित राज्य का विधान सभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है। राज्यपाल एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकते हैं, अगर समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि संविधान ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय कर दी है, लेकिन संसद द्वारा एक परिषद की वास्तविक ताकत तय की जाती है।
- 48 C  
Ex. आयोग कानून द्वारा सरकार की स्वायत्तता के रूप में स्थापित किया गया है, न कि संविधान द्वारा। एनएचआरसी खुद दोषियों को सजा नहीं दे सकता। यह अदलातों की जिम्मेदारी है। एचएचआरसी मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करने के लिए है। इस प्रकार, इसकी सिफारिशें न तो अदलातों के लिए बाध्यकारी हैं और न ही सरकार के। मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक एनएचआरसी को पत्र लिख सकता है। NHRC से संपर्क करने के लिए कोई शुल्क या कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है।
- 49 B  
Ex. एचसी के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित कोष से वसूले जाते हैं, लेकिन उनकी पेंशन चार्ज व्यय/कला 112(3) के रूप में देय होती है।
- 50 D  
Ex. कथन 1 और 4 अनिवार्य प्रावधान हैं और कथन 2 और 3 स्वैच्छिक प्रावधान हैं।
- 51 A  
Ex.
- 52 B  
Ex. अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। वे स्वयं व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।
- 53 D  
Ex. मूल रूप से, इसके 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता 30 हो गई। सभी तीस सदस्य केवल लोकसभा से हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। (कथन 1)  
यह संसद द्वारा मतदान किए जाने के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करता है, और इससे पहले नहीं। (कथन 3)
- 54 C  
Ex. स्पीकर प्रो टेम्प किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष ने नव-निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यालय खाली कर दिया। इसलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अध्यक्ष प्रो टेम्प के रूप में नियुक्त करता है। आमतौर पर, सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। (कथन 1)  
राष्ट्रपति स्वयं अध्यक्ष प्रो टेम्प को शपथ दिलाते हैं। (कथन 2)
- 55 C  
Ex. कथन 1 – राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में मिलने के लिए बुला सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में दोनों सदनों और उपाध्यक्ष के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि संयुक्त बैठक से उपसभापति भी अनुपस्थित रहता है, तो राज्यसभा का उप सभापति अध्यक्षता करता है। यदि वह अनुपस्थित है, तो इस तरह के अन्य व्यक्ति को संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बैठक की अध्यक्षता करता है।  
कथन 2 – संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण बिलों या वित्तीय बिलों पर लागू होता है, न कि मनी बिलों या संवैधानिक संशोधन बिलों पर।
- 56 D  
Ex. परिषद की अधिकतम ताकत विधानसभा की कुल ताकत का एक तिहाई और न्यूनतम ताकत 40 (कुछ अपवादों के साथ) तय की गई है। विधान परिषद का अध्यक्ष परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। परिषद अधिकतम 4 महीने की अवधि के लिए बिल में देरी कर सकती है।
- 57 B  
Ex. राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) और समवर्ती सूची (सूची-III) में उल्लिखित विषयों के संबंध में केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
- 58 B  
Ex.
- 59 A  
Ex. 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान पहला कानून आयोग स्थापित किया गया था।
- 60 B  
Ex. संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्यों की यूपीएससी द्वारा संसद द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यह यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के कार्मिक प्रणाली को भी रख सकता है। इसलिए यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- 61 D  
Ex.
- 62 C  
Ex. – कथन 1 और 5 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति हैं।  
– कथन 2, 3 और 6 विधायी शक्तियाँ हैं।  
– कथन 4 वित्तीय शक्ति है।
- 63 C  
Ex. वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया है।  
वेतन : मुख्य सूचना आयुक्त – 2.5 लाख  
अन्य सूचना आयुक्त – 2.25 लाख

- 64 D  
Ex. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार SC भी RTI के दायरे में आता है।
- 65 C  
Ex. नागरिकता के सम्बन्ध में संसद द्वारा पारित विधि राज्यों के लिए बाध्यकारी होगी।
- 66 C  
Ex. भारत में 'विधि का शासन' संकल्पना में विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा शामिल है इसलिए राज्य संरक्षणत्मक विभेद कर सकता है।
- 67 D  
Ex. संविधान का अनुच्छेद 19(2) में प्रावधानित मुक्ति युक्त निर्वचन आरोपित किये जा सकते हैं।
- 68 B  
Ex. अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत अभिदाता (subscriber) 60 वर्ष की आयु के उपरान्त अपने अंशदान के आधार पर एक न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। 18 से 70 वर्ष की आयु के समूह के सभी नागरिकों (एनआरआई सहित) के लिये उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी नागरिकों (एनआरआई सहित) के लिये उपलब्ध है।
- 69 C  
Ex.
- 70 C  
Ex. राज्य अचल संपत्ति अंधग्रहीत कर सकता है।
- 71 A  
Ex.
- 72 C  
Ex.
- 73 A  
Ex. परमादेश – हम आदेश देते हैं।  
प्रतिषेध – हम रोकते हैं।  
हैबियस कार्पस – सशरीर उपस्थित करो।  
उत्प्रेषण – प्रमाणित करते हैं।
- 74 C  
Ex. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में :  
– संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य  
– राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य  
– दिल्ली एवं पुडुच्चेरी विधायिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- 75 A  
Ex. महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने हेतु राष्ट्रपति को प्रेषित 14 दिनों की नोटिस की अवधि (ना कि 30 दिनों) की समाप्ति कर लिया जा सकता है।
- 76 B  
Ex. विधिक सरकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकते।
- 77 D  
Ex. धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्य सभा को कोई विशेष शक्ति नहीं है, लोक सभा की शक्तियाँ राज्य सभा पर प्रभाव होती है। इसलिए यह संघीय विशेषता नहीं है।
- 78 B  
Ex. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही लाया जा सकता है, ना कि राज्य सभा में।
- 79 B  
Ex. स्पीकर सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कृत्यों एवं निर्णयों के प्रति न्यायपालिका के समक्ष प्रश्नगत नहीं किये जा सकते, किन्तु लोक सभा सचिवालय के सचिव के रूप में कार्य एवं निर्णयों के प्रति प्रश्नगत किये जा सकते हैं।
- 80 D  
Ex. दल-बदल निरोधक कानून के अन्तर्गत अयोग्य ठहराये जाने का प्रावधान अनुच्छेद 102 (2) में है।
- 81 C  
Ex. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा चलाई गई स्कीम है। प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज इसका उद्देश्य है। सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिये क्रमशः 2% एवं 1.5% तथा बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किये जायेगा। ऋण प्राप्तकर्ता किसानों हेतु अनिवार्य है। पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया गया है।
- 82 A  
Ex. साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होती।
- 83 C  
Ex. धन विधेयक में अनुच्छेद 110 में दिये गये विषय शामिल किये जो हैं और करारोपण, करों को हटाया जाना या विनियमन अनुच्छेद 110 में वर्णित है।
- 84 A  
Ex. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में विधेयक पर अवरोध का समाधान साधारण बहुमत से किया जाता है, न कि विशेष बहुमत।
- 85 C  
Ex. दोनों सही है।
- 86 D  
Ex. सभी सही हैं।
- 87 C  
Ex. दोनों सही हैं।
- 88 C  
Ex. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन सम्बन्धित राज्य की संचित निधि पर आरित होता है, जकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
- 89 B  
Ex. – वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में वर्णित है।  
– बजट धन विधेयक होता है।  
– बजट केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 90 B  
Ex. सभी सही हैं।
- 91 C  
Ex. लेखानुदान द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की कुछ अनुदान की कुल माँग का लगभग 1/6 वाँ भाग अनुमोदित किया जाता है।
- 92 C  
Ex. सभी संकल्प, प्रस्ताव होते हैं किन्तु सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते।
- 93 D  
Ex. सभी सही हैं।

